

MR. SPEAKER: Let us confine ourselves to Kashmir.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But they have not confined to Kashmir.

MR. SPEAKER: But you can.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Yes, I can. In that case, I have nothing more to add to what I have already said.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE NINETY-SEVENTH REPORT

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): I beg to present the Ninety-seventh Report of the Public Accounts Committee on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-eighth Report relating to the Ministry of Finance.

PETITION RE. GRIEVANCES AND DEMANDS OF EMPLOYEES OF NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): I beg to present a petition signed by Shri N. R. Karmaran, Vice President, National Confederation of General Insurance Employees, Bombay regarding grievances and demands of employees of New India Assurance Company Ltd

12.38 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED TO REVIEW THE WORKING OF THE INDUSTRIAL UNDERTAKINGS

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बीमार औद्योगिक प्रतिष्ठान, बन्द हुए औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा उसमें लगी सरकार की पूंजी की तरफ मदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

यद्यपि वर्तमान सरकार की औद्योगिक नीति काफी उदात्त व्यावहारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में गति के साथ एक नई दिशा देने वाली है तथापि, पिछली सरकार के अनेक निर्णयों व तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति के फलस्वरूप देश में निरन्तर

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीमार होने की संख्या बढ़ती आ रही है। अतः सरकार को इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। हाल ही में इकात्मिक टाइम्स तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार दिसम्बर, 76 में लगभग 241 ऐसे यूनिट बीमार थे जिन में 1 करोड़ से अधिक का बैंक क्रेडिट था तथा यह संख्या सितम्बर, 77 में 270 हो गई। स्वाभाविक था कि इसी अनुपात में क्रेडिट धनांक भी बढ़ता और यह बढ़ कर 774 करोड़ हो गया, तथा दिसम्बर, 77 के अन्त तक यह राशि 858 करोड़ तथा यूनिट्स की संख्या 290 के लगभग हो गई। इस में एनटीसी द्वारा अधिग्रहीत मिलें सम्मिलित नहीं हैं न उनमें लगाई गई या लगी राशि ही इसमें जोड़ी गई है। वह राशि भी करोड़ों में है। साथ ही ऐसे अनेक माध्यम तथा छोटे यूनिट्स हैं जो बड़े उद्योगों की श्रेणी में तो नहीं हैं किन्तु उनमें भी अनुमानतः 200 से 300 करोड़ तक का क्रेडिट सम्मिलित है। हाल ही में चीनी मिलों के अधिग्रहण हेतु भी अध्यादेश प्रख्यापित किया गया जिसके त्रियान्वयन पर भी करोड़ों की राशि लगेगी ही। अतः यह आवश्यक है कि ममस्त स्थिति पर पुनर्विचार किया जाय तथा एक ऐसी नीति निर्धारित की जाय कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बंद होने अथवा बीमार या खराब होने की स्थिति त पट्टेच न बैंकों को या सरकार को करोड़ों रुपया धनांक करना पड़े, जिसे सरकार अन्य विकास कार्य में लगा कर सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है।

आशा है कि माननीय उद्योग मंत्री व वित्त मंत्री जो इस बारे में उठाये गए कदम व प्रस्तावित अन्य उपायों से मदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

(ii) SMALL SCALE INDUSTRIES SITUATED IN BACKWARD AND TRIBAL AREAS.

SHRI R. K. MHALGI (Thana): Mr. Speaker, with your kind permission, I want to make a statement on an urgent public matter under rule 377. Government is attributing very high priority to the development of industries in rural and particularly backward areas. The essential requisite for the success of such programme is the creation of favourable infrastructure, availability of raw materials competitively at cheaper rates, on an equitable basis so that it can stand competition with big manufacturers in the market. There are about 5,500 foundries in the country of which about 1500 are in the rural areas under the small scale sector.